

निर्णय बड़जलास श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़, जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 121 / 2025 प्रार्थनापत्र

दायर दिनांक :- 24 / 11 / 2025

निर्णय दिनांक :- 28 / 01 / 2026

अनवान

1. मिटालाल पिता तुलसीराम सुथार निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. मथुरालाल पिता गिरधारीलाल सुथार निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. जयराम पिता गिरधारीलाल सुथार निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पिता गिरधारी सुथार माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39
नियम 1-2 व सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

:: निर्णय ::

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त अनवान का एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का न्यायालय आपमें ठोस एवं सच्चे आधारों पर पेश कर दिया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमिया राजस्व ग्राम माता का गांव पटवार सर्कल नराणा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 104/1, 105/1, 108, 110/1, 111/1, 112, 114/1, 115, 116, 181/1, 184, 185, 187 कुल किता 13 कुल रकबा 32-07 बीघा भूमि स्थित है। उक्त पैरा संख्या दो में वर्णित कृषि भूमियों का प्रार्थीगण एवं विपक्षी के मध्य पूर्व में आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है, और प्रार्थीगण एवं विपक्षी उसी अनुसार अपने स्वामित्व व हिस्से की भूमियों पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर कृषि कार्य कर रहे हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षी के मध्य पूर्व में पारिवारिक बंटवाडा हुआ, उसी अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी ने मिल कर तहसीलदार साहब देवगढ़ के यहाँ अपनी अपनी सहमति से उपरोक्त सभी आराजियात का विभाजन करना



7/2
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

स्वीकार कर विभाजन हेतु सहमति स्वीकृति दी गई। जिसका आपसी सहमति से खातेदारी भूमि का विभाजन पत्र निष्पादित किया गया, जिस पर सभी खातेदारों (प्रार्थीगण एवं विपक्षी) के द्वारा अपने अपने हस्ताक्षर कर स्वीकार किया गया। उका विभाजन पत्र की पालना भी विपक्षी के द्वारा नहीं की जा रही है, जबकि उक्त विभाजन पत्र से प्रार्थीगण एवं विपक्षी पाबन्द है, विपक्षी के द्वारा किया जा रहा कृत्य अवैध व विधि विरुद्ध है। उक्त पैरा संख्या दो में वर्णित आराजियात के संबंध में विभाजन विलेख में यह स्पष्ट रूप से तय किया गया कि उक्त भूमियों में प्रार्थीगण एवं विपक्षी अपने अपने हिस्से पर काबिज रहेंगे, अन्य पक्षकारों का आने जाने का रास्ता, गाड़ी गडार एवं पानी का चोरा जिस किसी भी पक्षकार के खेतों से आती जाता है, उसे बन्द नहीं करेगा, कोई भी पक्षकार किसी भी पक्षकार का आने जाने का रास्ता, पानी का धोरा बन्द नहीं करेगा। आज से करीब 2 माह पूर्व विपक्षी के द्वारा प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि में आवागमन के रास्ते की भूमि के दोनों तरफ बनी पत्थरों की दीवार को तोड़ कर एवं उनके खेतों में आ जा रहे पानी के धोरे को बन्द कर रास्ता व पानी को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया, जिसके पश्चात प्रार्थीगण ने विपक्षी को ऐसा करने से रोका तो विपक्षी के द्वारा गाली गलोच कर प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगडा करने को आमादा हो गया व एलानियां धमकियां दे रहे हैं कि प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि में आने जाने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी के विरुद्ध ताफेसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी प्रार्थीगण के हिस्से की आराजियात में आने जाने के रास्ते व पानी के धोरे की भूमि में किसी प्रकार की रूकावट बाधा अवरोध पैदा नहीं करे तथा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट बाधा उत्पन्न नहीं करे व न ही रास्ते व पानी के धोरे की भूमि को खुर्द बुर्द ही करे। एवं वक्त आपसी बंटवारे के समय लिखित ईकरारनामे के अनुसार मौके पर शर्तों की पालना करे व वादीगण आपसी बंटवारा अनुसार मौके पर काबिज है उनके उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। दौराने वाद यदि विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमियों पर आने जाने के रास्ते व पानी के धोरे की भूमियों में रूकावट बाधा अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है तो आदेशात्मक आज्ञा से विपक्षी के खर्चे पर हटवाया जाकर पूर्ववत् स्थिति विवादग्रस्त भूमि की कायम कराई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। जवाब के विशेष उत्तर में उल्लेख किया कि प्रार्थना पत्र कि कलम संख्या एक में वर्णित आराजी नम्बर गत सेटलमेन्ट के आराजी नम्बर है, जबकी प्रार्थना पत्र में वर्तमान आराजी नम्बर का अंकन नहीं है। वर्तमान में पूर्व आपसी सहमती से भूमि का बंटवारा होने से प्रार्थीगण एवं विपक्षी का पृथक पृथक खाता कायम हो चुका है। विपक्षी विकलांग होकर चलने फिरने में असमर्थ है। केवल परेशान करने के नियत से दावा किया गया है। जो गलत है। पूर्व में प्रार्थीगण व विपक्षी कि शामलात भूमि का आपसी सहमती से बंटवारा हुआ



7/11
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्व

उसी अनुसार भूमि पृथक पृथक भूमि नाम पर दर्ज होकर वर्तमान में ग्राम माता का गांव कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 1.9300 हैक्टेयर भूमि विपक्षी के नाम दर्ज है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया अवलोकन से जाहिर आया कि भूमि का पूर्व में आपसी सहमति से विभाजन होकर पृथक खातेदारी स्थापित है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रतिवादी द्वारा उसके विधिक कब्जे में वास्तविक एवं तात्कालिक हस्तक्षेप किया गया हो। केवल मौखिक आरोप निषेधाज्ञा जैसी असाधारण राहत प्रदान करने हेतु पर्याप्त नहीं माने जा सकते। प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असफल रहा है। प्रार्थी की कथित हानि केवल अनुमानाधारित है। अतः सुविधा का संतुलन स्पष्टतः प्रतिवादी के पक्ष में है। प्रार्थी ऐसी किसी वास्तविक, तात्कालिक एवं अपूरणीय हानि को प्रमाणित नहीं कर सका है।

उपरोक्त विवेचन से उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी प्रथम दृष्टया अधिकार सिद्ध करने में असफल, सुविधा का संतुलन प्रतिवादी के पक्ष में, अपूरणीय क्षति सिद्ध नहीं होने से उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।



28/01/2026
(मोहकम सिंह सिमसिनवार R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
जिला राजसमन्द